

17/8/26

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संक्षेप में निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या नया 1 पुराना 1 की आराजी खसरा सं० 446 रकबा 0.0809 है० (पुराने खसरा सं० 309/1), खसरा सं० 293 रकबा 0.1214 है० (पुराने खसरा सं० 43/1), खसरा सं० 286 रकबा 0.5180 है० (पुराने खसरा सं० 174/1), खसरा सं० 287 रकबा 0.1781 है० (पुराने खसरा सं० 174/2), खसरा सं० 383 रकबा 0.1457 है० (पुराने खसरा सं० 157 मिन) वाके ग्राम ठिकरिया चारणान में स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थी काबूनी रूप से खातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी का खातेदार राजस्थान सरकार अंकित है। राजस्थान सरकार का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने के बावजूद उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। न ही अप्रार्थी का कब्जा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता श्री हरि सिंह गत 50 वर्ष से काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी काबिज काश्त चले आ रहे हैं। किन्तु उक्त आराजी पर अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से लगान पिलाई व अन्य आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है। हाल ही में अप्रार्थी के क्रमचारी प्रार्थी की भूमि पर आये और नाप चोक कर कहा कि इस भूमि पर पटवार मण्डल का निर्माण करेंगे। इस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर वो लोग वहा से चले गये। प्रार्थी की जानकारी के अनुसार उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाये जाने का आवेदन लम्बित होने के दौरान भी पटवार हल्का को जमीन आवंटन कर दी गयी एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो पायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा सं० 446 रकबा 0.0809 है० (पुराने खसरा सं० 309/1), खसरा सं० 293 रकबा 0.1214 है० (पुराने खसरा सं० 43/1), खसरा सं० 286 रकबा 0.5180 है० (पुराने खसरा सं० 174/1), खसरा सं० 287 रकबा 0.1781 है० (पुराने खसरा सं० 174/2), खसरा सं० 383 रकबा 0.1457 है० (पुराने खसरा सं० 157 मिन) वाके ग्राम ठिकरिया चारणान पर किसी प्रकार की कोई निर्माण या अन्य कोई गतिविधि नहीं करे। न ही प्रार्थी को भूमि से बेदखल करे। रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दोराने बहस पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी बाबत स्थगण आदेश चाहा गया है। वह आराजी सरकार खातेदार खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है जिस पर समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसे उक्त आराजी पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होने से खातेदार सरकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वाद वर्णित आराजी

17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड होने से उक्त आराजी पर समस्त खातेदारी अधिकारी राज्य सरकार में निहित है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा सं० 446 रकबा 0.0809 है० (पुराने खसरा सं० 309/1), खसरा सं० 293 रकबा 0.1214 है० (पुराने खसरा सं० 43/1), खसरा सं० 286 रकबा 0.5180 है० (पुराने खसरा सं० 174/1), खसरा सं० 287 रकबा 0.1781 है० (पुराने खसरा सं० 174/2), खसरा सं० 383 रकबा 0.1457 है० (पुराने खसरा सं० 157 गिन) बाकें ग्राम ठिकरिया चारणान पर केवल मात्र अधिकारी की हैसियत से काबिज काश्ल है जिसे उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार निहित नहीं होने से वह खातेदार सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

*my*